पवन कुमार

जल समाचार

जल संसाधनों का प्रबंधन जरूरी : शेखावत

केंद्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान मे एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में जल प्रबंधन पर आस्ट्रेलिया के सफल मॉडल की भारतीय परिदृश्य में उपयोगिता के तरीकों पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का सतत विकास और इसका कुशल प्रबंधन, जल सुरक्षा और आर्थिक विकास की कुंजी है। जलवायु परिवर्तन ने जल संसाधनों के असमान वितरण और उपलब्धता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसलिए स्थाई तरीके से जल संसाधनों के विकास पर जोर देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पहले ही ''हर खेत को पानी'' और ''न्यूनतम जल अधिकतम फसल'' सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इसके तहत कई परियोजनाएं लागू की हैं। जल जीवन मिशन के तहत ''हर घर नल का जल'' जैसे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल के क्षेत्र में चुनौतियों पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें सीमा विवाद में न पड़कर पूरे देश को एक मानकर समस्याओं पर मंथन करना होगा।

इसके साथ ही उपर्युक्त प्रबंधन के लिए वैज्ञानिकों अभियंताओं, ब्यूरोक्रेट्स आदि को मिलकर आवश्यक भूमिका निभाने की भी बात कही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने संस्थान परिसर में पौधा रोपित किया और सभागार का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया से डॉ. डीजे ब्लैकमोरे एवं डॉ. राबर्ट आदि ने भी तकनीकी सत्र में विचार रखे। वहीं प्रतिभागियों ने उनसे कई प्रश्न भी किए। इस मौके पर पेयजल एवं सिंचाई विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव, केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन एवं सदस्य, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रूड़की के निदेशक डॉ. शरद कुमार जैन, डॉ. संजय कुमार जैन, एनआईएच के वैज्ञानिक और विभिन्न संस्थानों से आए बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे।

पानी की मांग 2050 तक तीन गुना बढ़ जाएगी : कटारिया

केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि 2050 तक पानी की मांग तीन गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को देखते हुए जल संचय जरूरी है। सरकार **"हर घर नल से जल"** योजना के तहत लोगों के घरों में साफ पानी मुहैया करा रही है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान में दो दिवसीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन के अवसर पर पहुंचे राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि भारत में विश्व की सोलह फीसदी आबादी है जबकि पानी चार फीसदी ही है। इसमें से भी तीन फीसदी पानी खारा है। वर्षा जल के संचय की जरूरत है। अभी तक आठ फीसदी जल का ही संचयन हो पा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने कहा कि 2050 तक देश की जनसंख्या में पचास फीसदी शहरी और पचास फीसदी ग्रामीण आबादी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पानी की मांग तब तक तीन गुना बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए इस तरह की कार्यशाला बेहद जरूरी है।

स्वच्छता ही सेवा एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान विषय पर कार्यशाला

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रूड़की में दिनांक 11 सितम्बर, 2019 से 27 अक्टूबर 2019 तक **स्वच्छता ही सेवा एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान** के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी श्रृखंला में प्राथमिक विद्यालय न. 3 खंजरपुर में बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। सर्वप्रथम संस्थान के प्रांगण में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डॉ. एल.एन. ठकराल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार लोहनी एवं श्री वी.के. शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने स्कूल के

बच्चों के साथ मिलकर पौधारोपण किया तथा उनसे आह्वान किया गया कि वे स्कूल में सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा पेड़ों को संरक्षण देना तथा उनकी देख-भाल करना अपनी जिम्मेदारी समझें। डॉ. ए.के. लोहनी ने स्व्च्छता के सन्दर्भ में बच्चों को विभिन्न जानकारियां प्रदान की, उन्होंने अपने व्याख्यान में बच्चों को अपने आस-पास सफाई रखने के लिए प्रेरित किया तथा कहा यदि हम अपने आस-पास सफाई रखेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। डॉ. एल.एन ठकराल ने जल शक्ति अभियान के तहत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की तथा बच्चों को जल के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी का दायित्व है कि पानी का कम से कम प्रयोग कर उसका संरक्षण सुनिश्चित करें तथा व्यर्थ में बहने वाले पानी का उपयोग घर के पेड़ पौधों में करें। उन्होंने वृक्षों की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि यदि हमारा वातावरण हरा-भरा होगा तभी हमारा देश सुन्दर एवं स्वच्छ बनेगा। श्री वी.के. शर्मा ने स्कूली बच्चों को अपने आस-पास सफाई रखने तथा उससे होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी तथा कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। आस-पास के वातावरण को स्व्च्छ रखने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि अपने आस-पास सफाई करने से हम विभिन्न बीमारियों से बच सकते हैं। इं. सुमन गुर्जर ने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान पर अपना व्याख्यान दिया तथा अपील की कि हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया कि बाजार जाते समय कपड़े का थैला अवश्य लेकर जाएं और उसी में सामान लाएं और अनावश्यक प्लास्टिक के उपयोग से बचें। उन्होंने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों के लिए उनके स्कूल द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में जानकारी दी। श्री मुकेश शर्मा ने बच्चों को अपने शरीर की साफ-सफाई ठीक से करने तथा सवेरे उठकर योग करने के लिए प्रेरित किया। स्वच्छता विषय पर एक ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रथम पुरस्कार अमन, द्वितीय पुरस्कार अंकित तृतीय पुरस्कार मुस्तफा तथा प्रोत्साहन पुरस्कार सुफियान तथा अनमोल को प्रदान किये गये। कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने कार्यक्रम को संचालित करने वाली पूरी टीम तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी कर्मचारियों तथा प्रेस कर्मियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में राजेश नेमा, अवधेश शर्मा, अंचला प्रधान, सुनील यादव, आशा यादव, मुकेश कुमार, सुभाष किचलू, ओम प्रकाश, एन.के. वार्ष्णेय, श्रीमती किरण आहूजा, विपिन अग्रवाल, दयाल सिंह, आशीष कुमार बनर्जी, प्रदीप पंवार, नीलम बोहरा, श्याम कुमार, सुखपाल शर्मा, दिलीप, राजू, राकेश, अंकुश इत्यादि मौजूद रहे।

माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एनआईएच सभागार का उद्घाटन करते हुए

एनआईएच को यूपी में बड़ी जिम्मेदारी

हिंडन नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने नेशनल इंस्ट्टीयूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रूड़की के विशेषज्ञों की टीम को परियोजना बनाने का जिम्मा सौंपा है। टीम हिंडन नदी के उद्गम स्थल को लेकर पूरी परियोजना तैयार करेगी।

हिंडन में पानी की कमी ना रहे और उद्गम स्थल से ही उसमें पानी की आपूर्ति हो और अविरल धारा बहती रहे, इसके लिए छह विभागों के सात अधिकारियों की कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। हिंडन नदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम नदियों में से एक है और इसका उद्गम स्थल सहारनपुर में है।

कमिश्नर सीपी त्रिपाठी ने बताया कि हिंडन नदी के उद्गम स्थल को विकसित करने, उसके पर्यावरण में सुधार करने तथा आस-पास के स्थल पर उपलब्ध जल स्रोतों का अध्ययन करने तथा बैराज, जल संग्रहण यूनिटों की स्थापना, वाटर शेड स्ट्रक्चर्स, चैक डैम और तालाब आदि की परियोजना तैयार करने के लिए सात सदस्यों की समिति बना दी गई है। जिसमें छह विभागों के अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी रूड़की के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की टीम के साथ काम करेगी। वह अविलम्ब हिंडन उद्गम स्थल के आस-पास के क्षेत्रों का दौरा करके अध्यापन करेगी कि उद्गम स्थलों पर जलस्त्रोतों की क्षमता क्या है, उदगम स्थल के आस-पास छोटे-छोटे बैराज, जल संग्रहण बनाने की प्रक्रिया तथा पूरे क्षेत्र का डाटा एकत्रित कर परियोजना तैयार करेगी जिससे हिंडन नदी को पुनर्जीवित कर पूरे साल उसमें पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की द्वारा दिनांक 16-17 दिसंबर, 2019 आयोजित 6वीं राष्ट्रीय जल संगोष्ठी

राष्ट्रीय जलविज्ञान संथान, रूड़की द्वारा दिनांक 16-17 दिसंबर, 2019 को ''जल संसाधन एवं पर्यावरण'' विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रकृति के सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को समुचित बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1999 से हर चौथे वर्ष में नियमित रूप से किया जा रहा है। इस आयोजन की संपूर्ण कार्यवाही हिंदी में संचालित की जाती है।

उक्त संगोष्ठी के आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के सिलसिले में सर्वप्रथम निदेशक राजसं ने एक आयोजन समिति का गठन किया इसके पश्चात एक तकनीकी सलाहकार समिति का भी गठन किया गया जिसमें राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान तथा आई.आई.टी., रूड़की के कुल 22 अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया। आयोजित समिति ने 14 उप समितियों का गठन किया जिन्होंने इस संगोष्ठी के आयोजन से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं यथाः प्रायोजकता, प्रोसीडिंग्स/प्रमाण पत्रों की प्रिंटिंग, खान-पान व्यवस्था, वाहन एवं आवास व्यवस्था, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि, की-नोट स्पीकर के नाम, तकनीकी सत्र, प्रचार- प्रसार व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि जैसे मदों पर चर्चा-परिचर्चा कर तत्संबंधी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। इसके पश्चात संगोष्ठी के आयोजन से संबंधित एक पैम्फलेट तैयार किया गया जिसे

विभिन्न संस्थानों/विभागों/संगठनों/व्यक्ति विशेषों को भेजा गया और उनसे शोध पत्र आमंत्रित किए गए।

संगोष्ठी के लिए देश के भिन्न-भिन्न भागों से प्रबुद्ध वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं तथा शिक्षाविदों ने जल संसाधन तथा पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित अपने महत्वपूर्ण एवं उपयोगी शोध पत्र इस संगोष्ठी में प्रस्तुत किए जाने हेतु संप्रेषित किए जिनमें से उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण शोध पत्रों को तकनीकी समिति के सदस्यों द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात् संगोष्ठी में शामिल किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। कुल 69 शोध पत्रों को एक प्रोसीडिंग के रूप में संकलित कर प्रकाशित किया गया। संगोष्ठी में खर्च होने वाली राशि की व्यवस्था के लिए कुछ मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से प्रायोजकता हेतु अनुरोध किया गया, जिसमें से जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली तथा टी.एच.डी.सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश ने प्रायोजकता के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई। समितियों/उपसमितियों के सभी सदस्यों ने दी गई समस्त जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं मनोयोग से किया।

राष्ट्रीय जल संगोष्ठी का उद्घाटन समारोह दिनांक 16 दिसंबर, 2019 को आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली थे। उन्होंने जल, जल संसाधन एवं पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मदों पर बल देते हुए आग्रह किया कि आज भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व में जल संसाधनों के समुचित नियोजन एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज ''जल प्रबंधन'' हमारे सामने एक गम्भीर चुनौती के रूप में विद्यमान है। अतः जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन पर विशेष ध्यान देकर ही हम जल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अतः हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नियोजकों तथा पर्यावरणविदों को एकजुट होकर इस भावी त्रासदी का सफलतापूर्वक सामना करना है। जल की आपूर्ति एवं मांग तथा इसके महत्व को मद्दे नजर रखते हुए आज इसके समुचित प्रबंधन एवं सदुपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना परम आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आज जल का अंधाधुंध दुरूप्रयोग किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लोगों को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं से पार पाने का एक ही उपाय है कि जल की बचत की जाए और आवश्यकता के अनुरूप ही इसका उपयोग किया जाए, इसकी बर्बादी को रोका जाए। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार जल का दुरूपयोग जारी रहा तो भविष्य में हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

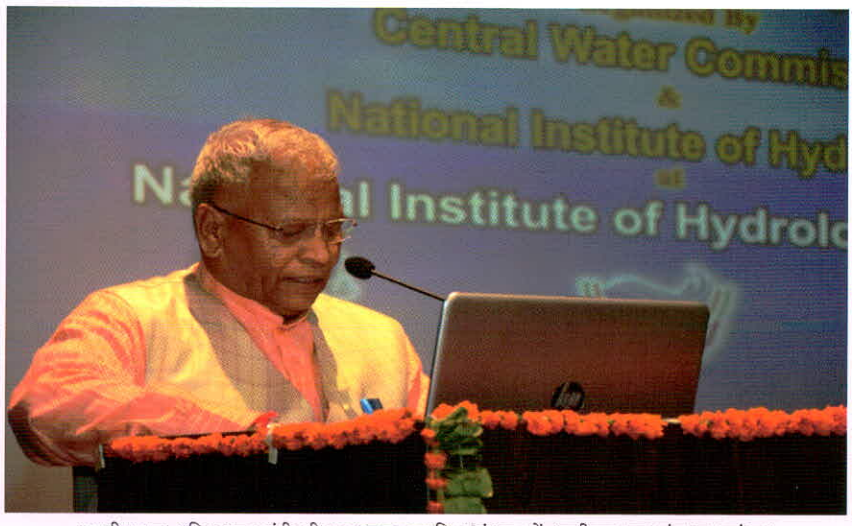

माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया संस्थान में "एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन" विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए

समारोह के दौरान सभी प्रतिभागियों में इस आयोजन के प्रति काफी उत्साह एवं जोश देखा गया जो तकनीकी लेखन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। संगोष्ठी में देश के भिन्न-भिन्न राज्यों यथा; मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं द्वारा जल प्रबंधन से जुड़ी भिन्न-भिन्न विषय-वस्तुओं पर कुल 56 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए।

शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण 8 तकनीकी सत्रों में किया गया। इसके अलावा जलविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त विद्वत जनों द्वारा प्रत्येक सत्र में एक-एक मूल अभिभाषण (की-नोट एड्रेस) भी प्रस्तुत किया गया। सभी शोध पत्र अत्यन्त ज्ञानवर्धक एवं सूचनापरक थे। विभिन्न सत्रों में प्रस्तुत किए गए शोध पत्रों के निष्कर्षों की समेकित अनुसंशाएं (recommedations) तैयार की गई और इनसे सभी को अवगत कराया गया तथा जल संसाधन एवं पर्यावरण से जुड़ी भावी समस्याओं के समाधान हेतु समय रहते समुचित उपाय किए जाने के सुझाव भी दिए गए।

राष्ट्रीय जल संगोष्ठी के प्रथम दिन प्रतिभागियों के स्वस्थ मनोरंजन हेतु स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ बाहर से आए कुछ प्रतिष्ठित कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी और दर्शको/श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया।

संगोष्ठी के दौरान मुख्य अतिथि के कर-कमलों द्वारा पुरस्कार/सम्मान भी प्रदान किए गए:-

- संस्थान के सतही जलविज्ञान प्रभाग को सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए राजभाषा चल वैजयंती पुरस्कार प्रदान किया गया।
- संस्थान द्वारा प्रारंभ की गई ''हिंदी में तकनीकी पुस्तक लेखन'' पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2016-17 के लिए तीन लेखकों को नकद पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।
- संस्थान में 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले 25 पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।
- संगोष्ठी के दौरान आठ सत्रों में प्रस्तुत किए गए शोध पत्रों में से प्रत्येक सत्र में एक-एक सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के लिए कुल आठ पुरस्कार प्रदान किए गए।

संगोष्ठी का समापन समारोह दिनांक 17 दिसंबर, 2019 को आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि टी.एच.डी. सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी.वी. सिंह थे। मुख्य अतिथि श्री सिंह ने समारोह में उपस्थित सभी प्रतिभागियों एवं श्रोताओं को जल संसाधन एवं पर्यावरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए आह्वान किया कि सभी जल के सरंक्षरण एवं समुचित उपयोग के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझें और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं को अपना सहयोग दें। उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रकार की संगोष्ठी चार वर्ष में एक बार न करके हर वर्ष आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर भी विशेष बल देते हुए कहा कि यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और इसके लिए हमें जटिल एवं बोझिल

शब्दों के प्रयोग से बचना होगा तथा प्रचलति शब्दों को प्रयोग में लाना होगा। उन्होंने अत्यन्त रोचक ढंग से अपनी बातें रखी तथा आज के परिप्रेक्ष्य में सभी उपस्थित सुधी जनों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने मानव जीवन में जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए तथा आज के बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन पर विशेष बल दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संगोष्ठी में सुझाई गई बातें देश के दीर्घकालिक विकास के संदर्भ में कारगर सिद्ध होंगी और इससे वैज्ञानिकों, अभियंताओं और शोधकर्ताओं को अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों में अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा।

हिंदी में तकनीकी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की द्वारा हिंदी में तकनीकी पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय जल जागरूकता पुरस्कार योजना" प्रारंभ की गई है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017, 01.01.2018 से 31.12.2018 तथा 01.01.2019 से 31.12.2019 के दौरान प्रकाशित तकनीकी पुस्तकें आमंत्रित की गई हैं। इस योजना के तहत पुस्तकों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

प्रथम - मौलिक रूप से हिंदी में प्रकाशित तकनीकी पुस्तकें

द्वितीय श्रेणी - हिंदी में प्रकाशित अनूदित तकनीकी पुस्तकें

पुरस्कार योजना हेतु स्वीकार्य पुस्तकों के विषयः

(क) जलविज्ञान

(ख) जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जल

(ग) कृषि, वन, पर्यावरण के क्षेत्र में जल की भूमिका

पुरस्कार राशि

(प्रथम श्रेणी के अंतर्गत)

प्रथम - 50,000/- रू. एवं स्मृति चिह्न

द्वितीय - 30,000/- रू. एवं स्मृति चिह्न

तृतीय - 20,000/- रू. एवं स्मृति चिह्न

(द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत)

प्रथम - 50,000/- रू. एवं स्मृति चिह्न

द्वितीय - 30,000/- रू. एवं स्मृति चिह्न

तृतीय - 20,000/- रू. एवं स्मृति चिह्न

पात्रता एवं सामान्य शर्तें

1. भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।

2. एक लेखक एक से अधिक प्रविष्टियां भी भेज सकता है। पुस्तक में एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में पुरस्कार राशि प्रथम लेखक को प्रदान की जाएगी। सह-लेखकों को पुरस्कार राशि के वितरण की जिम्मेवारी समिति की न होकर प्रथम लेखक की होगी।

3. किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होगी।

4. उपर्युक्त विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की को दी जाए।

5. योजना के अंतर्गत कलैन्डर वर्ष 2017, 2018 तथा 2019 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं। पुस्तक का विषय किसी पी.एच.डी. शोध के लिए शामिल न किया गया हो।

6. लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।

7. पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ (कम से कम 50 हजार शब्द) की होनी चाहिए। इसमें फोटोग्राफ एवं संदर्भों के पृष्ठ शामिल नहीं होंगे।

8. पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करने पर केवल तृतीय श्रेणी (वातानुकूलित) (3 ए.सी.) का रेल किराया दिया जाएगा।

9. पुरस्कृत लेखक तीन वर्षों के उपरांत ही इस योजना में पुनः भाग ले सकते हैं।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पुस्तक किसी अन्य पुस्तक/लेखों आदि से अनूदित, इनसे नकल की गई नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया गया तो पुस्तक स्वीकार नहीं की जाएगी और यदि पुरस्कार देने के बाद ऐसा पाया गया तो संस्थान को पूरा अधिकार होगा कि वह पुरस्कार की धनराशि लेखक से वापिस ले। ऐसे विवाद का न्यायिक निपटान रूड़की क्षेत्र में होगा।

11. ऐसी पुस्तकें जो किसी पाठ्यक्रम के लिए या किसी भी सरकारी विभाग/एजेंसी से प्राप्त अनुदान/सहायता से लिखी/प्रकाशित की गई हों, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

प्रविष्टियां भेजने की विधि

(I) प्रविष्टियां राजसं वेबसाइट में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे भरे हुए) के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की 05 प्रतियां भेजी जाएं। पुस्तक वापिस नहीं की जाएंगी।

(iii) प्रथम लेखक अपनी प्रविष्टियां निर्धारित तिथि तक अवश्य भिजवा दें। इस तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

पुरस्कार संबंधी घोषणा

(i) पुरस्कार संबंधी निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी।

(ii) पुरस्कार वितरण राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

सामान्य

पुरस्कार के लिए पुस्तक के मूल्यांकन के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

योजना के बारे में सूचना राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान की वेबसाइट www.nihroorkee.gov.in पर भी उपलब्ध है।

इस योजना में पांडुलिपि (हस्तलिखित अथवा टंकित) पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।

प्रविष्टि भेजने का पताः

निदेशक राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान,
जलविज्ञान भवन,
रूड़की-247 667 (उत्तराखंड)

संर्पक करेः
पवन कुमार
परामर्शदाता जल चेतना
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान।
मो.नं. 9359729313